

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 06-09-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 06 Sep, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 03 Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims	विदेश मंत्री अमेरिकी टैरिफ पर ब्राज़ील के नेतृत्व वाले ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे: विदेश मंत्रालय
Page 05 Syllabus : GS 3 : Science and Technology/ Prelims	भारत परमाणु प्रतिरोध और ड्रोन युद्ध क्षमताओं को मज़बूत करने की योजना बना रहा है
Page 06 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	एक नया अध्याय: पर्यावरण अनुपालन की सभी स्तरों पर निगरानी ज़रूरी
Page 07 Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims	समस्याओं का समाधान, भारत की विकास क्षमता का दोहन
Page 11 Syllabus : GS 2 & 3 : International Relations & Indian Economy / Prelims	निर्यातकों का कहना है कि वैश्विक से घरेलू बाज़ार में बदलाव आसान नहीं
Page 06 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : International Relations	बहुध्रुवीय विश्व में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की पहल पर आयोजित वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे। यह बैठक अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए ऊँचे आयात शुल्क (टैरिफ) के संदर्भ में बुलाई गई है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का यह कदम न केवल एकजुट प्रतिक्रिया का संकेत देता है बल्कि भारत की आगामी ब्रिक्स अध्यक्षता के कारण विशेष महत्व भी रखता है।

मुख्य भाग

1. अमेरिकी टैरिफ का परिप्रेक्ष्य

- 6 अगस्त को अमेरिका ने ब्राजील और भारत से आने वाले सामानों पर 50% टैरिफ, चीन व दक्षिण अफ्रीका पर 30% तथा इंडोनेशिया पर 19% शुल्क लगाया।
- रूस और ईरान जैसे देशों पर अपेक्षाकृत कम 10% शुल्क लगाया गया है।
- यह कदम संरक्षणवादी (protectionist) नीति को दर्शाता है और वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है।

ब्राजील की पहल

- राष्ट्रपति लूला ने सभी ब्रिक्स देशों से मिलकर एक "साझा रणनीति" बनाने की अपील की है।
- यह ब्राजील का प्रयास है कि ब्रिक्स को वैश्विक आर्थिक शासन में संतुलनकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

External Affairs Minister to join Brazil-led BRICS virtual summit on U.S. tariffs: MEA

Suhasini Haidar
NEW DELHI

External Affairs Minister S. Jaishankar will represent India at a virtual summit of BRICS nations on Monday, the Ministry of External Affairs said here on Friday, announcing India's participation in the meeting convened by Brazil President Lula da Silva to discuss tariffs imposed by the U.S.

The summit, which is bound to irk the U.S. government, comes days after Prime Minister Narendra Modi's visit to China for the SCO summit and conversation with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, which U.S. officials criticised.

Countries taking part

Brazilian officials have not confirmed how many of the 11-member BRICS grouping of emerging economies will participate in the summit and at what level. Shortly after U.S. tariffs were imposed on August 6, Mr. Lula had called the Mr. Modi and said he would speak to each of the BRICS members to rally support



S. Jaishankar

towards forming a "common" plan to deal with the move.

On Friday, the Kremlin's spokesperson confirmed that Mr. Putin would take part in the summit, and sources said they expected other confirmations over the weekend.

"From [India's] side, it will be the External Affairs Minister [S. Jaishankar] who will be participating in it," said MEA spokesperson Randhir Jaiswal when asked at a weekly briefing. "This BRICS summit is at the leaders' level," he added, but did not clarify why Mr. Modi would not attend the meeting.

India is the next Chair of the BRICS grouping, and will host the summit of

countries including Brazil, Russia, India, China, South Africa and new members Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

The Brazilian Ministry of Foreign Affairs has not yet announced the specific agenda of the meeting to be held on Monday. However, local media reported that the summit would discuss the impact of U.S. tariffs on global trade, and measures to strengthen multilateralism in order to counter the effects of unilateral economic measures.

The U.S. has imposed 50% tariffs on goods from Brazil, like India, the two countries with the highest levies worldwide. China and South Africa also face high 30% tariffs, and Indonesian goods are levied 19% tariffs, with a waiver for its most important agricultural exports such as palm oil, cocoa and rubber.

All other BRICS nations including Russia and Iran, which are among the most heavily sanctioned countries, are on the lowest rung of 10% tariffs.

भारत की संतुलित रणनीति

- भारत ने प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री को भेजने का निर्णय लेकर एक सतर्क रुख अपनाया है।
- भारत अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित अवश्य है, परंतु साथ ही अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी, रक्षा और इंडो-पैसिफिक साझेदारी भी बनाए रखना चाहता है।

भूराजनीतिक पहलू

- यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद हो रही है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने शी चिनफिंग और पुतिन से मुलाकात की थी।
- रूस, चीन और ईरान जैसे देशों की सक्रिय भागीदारी से यह चर्चा "अमेरिकी वर्चस्व" के विकल्प की झलक देती है।
- भारत के लिए चुनौती यह है कि वह ब्रिक्स में अपनी भूमिका निभाए परंतु "अमेरिका-विरोधी धड़े" का हिस्सा न दिखे।

वैश्विक शासन पर प्रभाव

- विस्तारित ब्रिक्स (11 सदस्य) विश्व की जीडीपी और व्यापार का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है।
- यह बैठक दर्शाती है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएँ एक अधिक न्यायपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहती हैं।
- हालाँकि, आंतरिक मतभेद और विभिन्न आर्थिक-रणनीतिक प्राथमिकताएँ एकीकृत प्रतिक्रिया को सीमित कर सकती हैं।

निष्कर्ष

अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सामूहिक आवाज़ को रेखांकित करता है। भारत के लिए यह अवसर है कि वह एक ओर अमेरिकी संरक्षणवाद के विरुद्ध अपनी चिंताओं को व्यक्त करे और दूसरी ओर रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे। दीर्घकालिक दृष्टि से, यह घटनाक्रम वैश्विक आर्थिक शासन में शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों का प्रतीक है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो ब्रिक्स (BRICS) से संबंधित हैं:

1. भारत ब्रिक्स का अगला अध्यक्ष होगा।
2. हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार कर इसमें मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को शामिल किया गया।
3. पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Ans : a)

UPSC Mains Practice Question

Ques: ब्राज़ील-नेतृत्व वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अमेरिका के टैरिफ़ पर भारत की भागीदारी उसके सामरिक स्वायत्तता और आर्थिक हितों के बीच संतुलनकारी भूमिका को दर्शाती है। विवेचना कीजिए। **(150 Words)**

भारत द्वारा जारी प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य एवं क्षमता रोडमैप (TPCR-2025) आने वाले 15 वर्षों के लिए सैन्य तैयारी का खाका प्रस्तुत करता है। इस दस्तावेज़ में परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत बनाने के साथ-साथ ड्रोन युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमताओं पर विशेष बल दिया गया है। यह कदम बदलते युद्ध के स्वरूप को दर्शाता है तथा भारत की दोहरी प्राथमिकताओं — रणनीतिक प्रतिरोधक स्थिरता और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता — को सामने लाता है।

India plans to strengthen nuclear deterrence, drone warfare capabilities

Saurabh Trivedi
NEW DELHI

India has set out an ambitious plan to reinforce its nuclear deterrence and expand drone warfare capabilities under the Technology Perspective and Capability Roadmap (TPCR-2025), a 15-year blueprint for military preparedness.

The document highlights measures to sustain credible nuclear deterrence through survivability systems and advanced delivery platforms. While it avoids reference to specific warhead technologies, it outlines future acquisitions such as nuclear command-and-control infrastructure, radiation detection tools, and mobile decontamination units. Unmanned ground vehicles for chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) reconnais-



Ready for action: TPCR-2025 envisages adaptive jamming systems, electronic denial bubbles to neutralise attacks by hostile drones. PTI

sance are also on the agenda, aimed at strengthening protection against potential nuclear or chemical fallout.

On the aerial front, the Army has projected requirements for stealth remotely piloted aircraft with ranges of up to 1,500 km and altitudes of 60,000 feet. These drones would carry electronic warfare payloads; nuclear, biologi-

cal, and chemical detection equipment, and even guide artillery fire.

Loitering munition

The road map also places emphasis on loitering munitions, designed to carry out precision strikes with artificial intelligence-enabled targeting and reusable warhead systems. In addition, integrated surveillance and targeting drones

are expected to boost the battlefield capabilities of mechanised forces.

India is also preparing for the emerging threat of hostile drone swarms.

The TPCR-2025 envisages adaptive jamming systems and electronic denial bubbles with a 15 km radius to neutralise such attacks, underscoring the rising importance of electronic warfare in modern combat.

Officials said the initiatives were closely aligned with the government's self-reliance push in defence production by reducing dependence on foreign imports.

With the road map, India has signalled a strategic shift towards integrated deterrence – combining nuclear resilience, electronic warfare, and unmanned strike platforms – to strengthen national security in the coming decades.

मुख्य भाग

1. विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना

- TPCR-2025 में जीवित रहने की क्षमता (survivability systems) और उन्नत डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म पर ज़ोर है।
- इसमें परमाणु कमान और नियंत्रण अवसंरचना, विकिरण पहचान प्रणाली, मोबाइल डी-कंटैमिनेशन यूनिट और CBRN (रासायनिक, जैविक, विकिरणीय, परमाणु) टोही के लिए मानव रहित ज़मीनी वाहन शामिल हैं।
- दस्तावेज़ में नए वारहेड का उल्लेख नहीं है, बल्कि मौजूदा प्रतिरोधक क्षमता को लचीला और मज़बूत बनाने पर ध्यान है।

ड्रोन युद्धक क्षमता का विस्तार

- सेना ने 1,500 किमी की दूरी और 60,000 फीट की ऊँचाई तक उड़ने वाले स्टेल्थ ड्रोन की आवश्यकता बताई है।
- ये ड्रोन बहुउद्देशीय होंगे: इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरण, CBRN सेंसर ले जाने और तोपखाने की फायरिंग को मार्गदर्शन देने में सक्षम।
- एआई-सक्षम loitering munitions और पुनः प्रयोग योग्य वारहेड सटीक एवं स्वचालित हमले की दिशा में कदम हैं।
- एकीकृत निगरानी व लक्ष्य निर्धारण ड्रोन यंत्रीकृत बलों की क्षमताओं को बढ़ाएँगे।

शत्रु ड्रोन खतरों का मुकाबला

- रोडमैप ड्रोन स्वॉर्म (ड्रुंड) के बढ़ते खतरे को स्वीकार करता है।
- समाधान के तौर पर adaptive jamming systems और 15 किमी त्रिज्या वाले electronic denial bubbles विकसित करने की योजना है।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता

- ये सभी पहलें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ी हैं।
- ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और CBRN तकनीक में स्वदेशी अनुसंधान एवं उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

रणनीतिक निहितार्थ

- यह कदम एकीकृत प्रतिरोधक (Integrated Deterrence) की दिशा में है — जिसमें परमाणु लचीलापन, मानव रहित प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमता का समावेश है।
- भारत को बहु-आयामी युद्धक्षेत्र के लिए तैयार करता है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व पारंपरिक शक्ति जितना ही निर्णायक होगा।
- इससे राज्य और गैर-राज्य दोनों प्रकार के खतरों, विशेषकर ड्रोन आधारित असममित युद्ध का सामना करने की क्षमता मज़बूत होगी।

निष्कर्ष

TPCR-2025 यह दर्शाता है कि 21वीं सदी के युद्ध तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व से परिभाषित होंगे। भारत ने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, ड्रोन युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक शक्ति को एकीकृत कर दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने का संकेत दिया है। किंतु इसके लिए निरंतर स्वदेशी अनुसंधान, निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्पष्ट सैन्य सिद्धांत आवश्यक होंगे ताकि यह रोडमैप वास्तविक युद्धक क्षमता में बदला जा सके।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: भारत की प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य एवं क्षमता रोडमैप (TPCR-2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केवल परमाणु वारहेड विकास पर केंद्रित है।
2. इसमें स्टेल्थ ड्रोन और loitering munitions की योजना शामिल है।
3. इसमें ड्रोन स्वॉर्म का मुकाबला करने के लिए adaptive jamming systems का प्रावधान है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Ans : b)

UPSC Mains Practice Question

Ques: TPCR-2025 के उद्देश्यों की प्राप्ति में स्वदेशी रक्षा उत्पादन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता को तेज़ करने के उपाय सुझाइए। **(150 Words)**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों और परियोजनाओं द्वारा पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है। अब तक यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों पर थी, लेकिन संसाधनों और क्षमता की कमी से ये संस्थान अपेक्षित स्तर पर निगरानी नहीं कर पा रहे थे।

मुख्य बिंदु

1. सुधार की आवश्यकता

- वर्तमान प्रणाली में जनशक्ति और तकनीकी संसाधनों की कमी।
- बड़ी संख्या में परियोजनाओं और उद्योगों पर निगरानी कठिन।
- जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन अक्सर अनदेखे रह जाते हैं।

पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

- निजी एजेंसियों को पर्यावरण ऑडिटर के रूप में मान्यता और लाइसेंस दिया जाएगा।
- ये ऑडिटर कंपनियों की पर्यावरण कानूनों और प्रदूषण नियंत्रण की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से अनुपालन की जाँच करेंगे।
- ग्रीन क्रेडिट नियमों से जुड़ाव, जिसके तहत जल प्रबंधन, वनीकरण, कचरा प्रबंधन आदि गतिविधियों पर ट्रेडेबल क्रेडिट दिए जाएंगे।
- कंपनियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन का लेखा-जोखा रखना होगा।

संभावित लाभ

- जनशक्ति और संसाधन की कमी को दूर करने में मदद।
- अनुपालन प्रणाली में व्यावसायिकता और मानकीकरण।
- ग्रीन क्रेडिट जैसी प्रोत्साहन व्यवस्था से कंपनियाँ अधिक सतत प्रथाओं को अपनाएँगी।

A new leaf

Environmental compliance needs to be monitored at all levels

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has brought into effect a set of rules called the Environment Audit Rules, 2025, that allows the vital activity of environmental monitoring and auditing to go beyond the remit of State Pollution Control Boards. The rules will largely scrutinise whether industrial units are compliant with environmental regulation. The overall framework for monitoring and compliance within the existing environmental framework is presently supported by the Central Pollution Control Board, the Regional Offices of the Environment Ministry, and the State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees. They have, however, been facing significant constraints in terms of manpower, resources, capacity and infrastructure. "These limitations have hampered their ability to comprehensively monitor and enforce environmental compliance across the vast number of projects and industries operating nationwide," said a press statement by the Environment Ministry. This scheme aims to bridge the manpower and infrastructure deficits faced by regulatory authorities, thereby strengthening the effective implementation of environmental compliance mechanisms.

Under the new rules, private agencies can get themselves accredited as auditors. Much like chartered accountants, environment auditors can get themselves licensed and be authorised to evaluate the compliance of projects with environmental laws and their adherence with best practices in the prevention, control and abatement of pollution. Environmental regulation has, in recent years, transcended policing and bookkeeping. Given that human-caused climate change is seen as a problem that nations must collectively fix, new dimensions to environmental regulations have emerged. Thus, audits undertaken by these agencies can also be used for compliance with 'Green Credit Rules', under which individuals and organisations can gain tradeable 'credits' for afforestation, sustainable water management and waste management among other activities. Beyond industrial units, nearly every company in India will have to account for its direct and indirect carbon emissions. This will entail fairly complex accounting practices, which are beyond what Pollution Control Board officials can handle. However, preparing for the future should not be at the expense of compromising core responsibilities. It is usually at the district, block and panchayat levels that the most flagrant environmental travesties abound, which escape notice usually because of the lack of trained staff. The new regime must seek to empower them too.

- वैश्विक कार्बन अकाउंटिंग और ESG रिपोर्टिंग के लिए भारत की तैयारी।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- यदि ऑडिटर कंपनियों से सीधे भुगतान लेंगे तो हितों का टकराव हो सकता है।
- केवल कॉर्पोरेट स्तर पर ध्यान देने से स्थानीय स्तर की समस्याएँ नज़रअंदाज़ हो सकती हैं।
- पारदर्शिता और कठोर निगरानी की कमी से ऑडिट "रबर स्टाम्प" जैसा बन सकता है।
- ज़मीनी स्तर पर संस्थागत क्षमता निर्माण आवश्यक।

निष्कर्ष

पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 पर्यावरणीय शासन में एक प्रगतिशील बदलाव है। इससे सरकारी निगरानी को निजी विशेषज्ञता का सहारा मिलेगा और अनुपालन प्रणाली अधिक मजबूत बनेगी। परंतु इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि मान्यता प्रक्रिया कितनी सख्त है, पारदर्शिता कितनी सुनिश्चित की जाती है और जमीनी स्तर पर संस्थानों को कितना सशक्त बनाया जाता है। केवल कॉर्पोरेट स्तर नहीं बल्कि स्थानीय समुदायों तक पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करना ही इन नियमों की वास्तविक कसौटी होगी।

UPSC Prelims Practice Question

Ques : पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इनके अंतर्गत निजी एजेंसियों को पर्यावरण ऑडिटर के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
2. पर्यावरणीय ऑडिट को ग्रीन क्रेडिट नियमों के अनुपालन हेतु भी उपयोग किया जा सकता है।
3. केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही इन नियमों के अंतर्गत ऑडिट करने का अधिकार है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Ans : a)

UPSC Mains Practice Question

Ques: निजी ऑडिटरों के माध्यम से पर्यावरणीय अनुपालन का व्यवसायीकरण एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु यह जमीनी स्तर पर उत्तरदायित्व को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। (150 Words)

56वीं जीएसटी परिषद की बैठक (सितंबर 2025) में किए गए सुधारों को जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। दरों के सरलीकरण, विसंगतियों को दूर करने, अनुपालन को आसान बनाने और विवाद निवारण को मजबूत करने के ज़रिए सरकार ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को अधिक पूर्वानुमेय, न्यायसंगत और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ये बदलाव केवल कर दरों में संशोधन नहीं हैं, बल्कि संरचनात्मक सुधार हैं, जिनसे भारत की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता खुल सकती है।

Fixing problems, unlocking India's growth potential

India's economic journey has always been shaped by bold reforms, and the latest set of Goods and Services Tax (GST) measures announced at the 56th GST Council meeting on September 3, 2025, may well prove to be one of the most consequential yet. For years, businesses and policymakers alike have called for simplification, predictability, and fairness in India's indirect tax regime. With the latest decisions – streamlining rates, correcting anomalies, easing compliance and strengthening dispute resolution – the government has delivered a package that balances ambition with pragmatism.

What makes this moment special is not just the scope of the changes but also the collaborative spirit behind them. The result is what many are calling GST 2.0 – a reform designed not merely to fix today's problems but also to unlock India's growth potential for the decade ahead.

Relief for many income groups

Essentials such as soap, toothpaste, hair oil, shampoo, kitchenware and packaged foods now fall under lower tax brackets, immediately easing household budgets and boosting demand in sectors that employ millions. For housing, reduced GST on cement and construction materials will bring homes within reach for more families, supporting the government's 'Housing for All' mission while stimulating allied industries such as steel, tiles, sanitaryware and paints. Infrastructure projects too will benefit from lower costs of inputs, improving project viability and freeing capital for expansion.

Life-saving drugs and critical medical devices have been moved to nil or 5% GST, cutting treatment costs and expanding access for patients. In a country that has emerged as a global hub for affordable medicines, this is both a social and economic win.

Labour-intensive industries such as textiles, handicrafts, leather, footwear, and toys – stand to gain from lower rates that protect margins, safeguard livelihoods, and create jobs in semi-urban and rural clusters. The automotive sector, a key driver of growth, will also see a



Harsha Vardhan Agarwal

is President,
Federation of Indian
Chambers of
Commerce and
Industry (FICCI)

GST 2.0 is both
a tax reform
and the start of
a new chapter
in the
growth journey

boost as now more affordable small cars, motorcycles, buses and trucks will encourage demand and investment in auto-manufacturing hubs.

Helping exporters and MSMEs

The rationalisation of rates would also help exporters. Long-standing distortions created by inverted duty structures in textiles, fertilizers and renewables are finally being corrected. This will make Indian products more competitive globally while reducing import dependence. Export-heavy sectors such as handicrafts, leather, and engineering goods – most driven by micro, small and medium enterprises (MSME) – are well placed to gain benefits. Lower duties on capital goods and intermediates will also promote local value addition, directly supporting the 'Make in India' initiative.

One of GST's biggest challenges has always been litigation. Interpretational disputes, classification complexities and uncertainty over tax treatment have burdened businesses and clogged up the system. Rationalisation addresses this by simplifying slabs and harmonising rates for similar goods. Clarifications on intermediary services and post-sale discounts further reduce ambiguity, bringing long-awaited relief to service exporters and aligning tax rules with commercial practices.

Small exporters will welcome the decision to remove thresholds for refunds on low-value consignments. This ensures fairer treatment for courier and e-commerce players, where liquidity pressures are acute. Faster, more reliable refunds will ease working capital challenges and encourage reinvestment in growth.

Perhaps the most path-breaking measure is the Simplified GST Registration Scheme for Small and Low-Risk Businesses. By introducing automated approvals within three days, the government has dramatically reduced entry barriers, which will cut compliance costs, encourage formalisation, and allow MSMEs to expand into new markets with greater ease.

Given that MSMEs are the backbone of India's economy – contributing to jobs, exports and

innovation – the significance of this step cannot be overstated.

Institutional reform has also received a boost with the operationalisation of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT). By enabling faster and fairer resolution of disputes, GSTAT will strengthen confidence in the system and reduce case backlogs. This signals that GST is not just about revenue collection but also about building a fair and predictable tax framework that businesses can trust.

The broader message is equally important. The streamlined two-rate GST structure (a standard rate of 18% and a merit rate of 5% with a special de-merit rate of 40% for a select few goods and services) aligns India more closely with global best practices, moving it to the kind of tax regime that advanced economies employ. For international investors, the reforms send a strong signal of policy stability, predictability and ease of doing business. In a world where global supply chains are being reconfigured, India is positioning itself not just as a vast market but also as a reliable and competitive investment destination.

A pathway to economic expansion

Of course, reforms are never the end of the road. Implementation will be key, and challenges such as delays and procedural complexities still need attention. But what stands out is the intent. The government has shown that it is listening to industry, willing to act decisively, and committed to building a tax system that fuels, rather than impedes, growth.

GST 2.0 is more than just a tax reform. It is an economic reform that promises to boost consumption, empower MSMEs, strengthen competitiveness, and reinforce India's growth momentum. It lays the foundation for India's next phase of economic expansion.

The story of GST has always been one of bold ambition. With these reforms, India has taken a decisive step toward realising that ambition. For businesses, consumers and policymakers alike, this is not just an adjustment of rates. It is the start of a new chapter in India's growth journey.

मुख्य भाग

1. घरेलू उपभोक्ताओं को राहत

- साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, रसोई सामान और पैकड फूड जैसी आवश्यक वस्तुएँ कम स्लैब में → परिवारों के बजट पर राहत और माँग में वृद्धि।
- सीमेंट व निर्माण सामग्री पर दरें घटने से → सभी के लिए आवास मिशन को बल, साथ ही स्टील, टाइल्स, पेंट जैसे सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन।
- जीवनरक्षक दवाएँ और उपकरण 0% या 5% जीएसटी स्लैब में → इलाज सस्ता, भारत की सस्ती दवाइयों के वैश्विक केंद्र की पहचान मज़बूत।

रोज़गार-सृजन क्षेत्रों को प्रोत्साहन

- वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा, जूते-चप्पल और खिलौनों जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों पर कम दरें → ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में रोज़गार सुरक्षा।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर → छोटे वाहन, बाइक, बस और ट्रक सस्ते होने से माँग और निवेश में वृद्धि।

निर्यातकों और MSME को लाभ

- वस्त्र, उर्वरक व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में उल्टे शुल्क ढाँचे (Inverted Duty) को ठीक किया गया → निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार।
- छोटे पार्सल पर रिफंड सीमा हटने से ई-कॉमर्स व छोटे निर्यातकों की नकदी समस्या हल होगी।
- पूंजीगत सामान व मध्यवर्ती वस्तुओं पर कम शुल्क → मेक इन इंडिया को बढ़ावा।
- सरल पंजीकरण योजना में 3 दिन में स्वचालित अप्रूवल → अनुपालन लागत घटेगी, MSME का औपचारिकरण तेज़ होगा।

संस्थागत व संरचनात्मक सुधार

- जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की स्थापना → विवादों का त्वरित निपटान, न्यायिक बोझ कम, कारोबार में विश्वास बढ़ेगा।
- मध्यस्थ सेवाओं व बिक्री-बाद छूट पर स्पष्टता → कर प्रणाली में अस्पष्टता घटेगी।
- तीन दरों वाला सरल ढाँचा (5%, 18% और 40% डिमेरिट) → वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब, निवेशकों को स्थिरता का संकेत।

रणनीतिक महत्व

- कर प्रणाली में Ease of Doing Business और स्थिरता → वैश्विक निवेश आकर्षित करने में सहायक।
- MSME को प्रोत्साहन → रोज़गार, निर्यात और नवाचार में वृद्धि।
- राजस्व व विकास में संतुलन → भारत की दीर्घकालिक वृद्धि आकांक्षाओं के अनुरूप।

निष्कर्ष

जीएसटी 2.0 केवल कर सुधार नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक सुधार है। दरों को सरल बनाकर, विवाद घटाकर और उपभोक्ताओं व व्यवसायों को राहत देकर यह भारत की विकास यात्रा को नई दिशा देता है। हालांकि, इसका प्रभावी क्रियान्वयन, जीएसटी नेटवर्क की डिजिटल क्षमता में सुधार और तेज़ रिफंड प्रक्रिया जैसी चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि इन सुधारों को सही ढंग से लागू किया गया तो जीएसटी वास्तव में एक विकास-प्रेरक व्यवस्था बन सकता है, जो भारत को बड़ा उपभोक्ता बाज़ार ही नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य भी बनाएगा।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: जीएसटी 2.0 सुधारों (2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी को 5% अथवा शून्य कर दिया गया है।
2. वस्त्र और उर्वरक क्षेत्रों में उल्टे शुल्क ढाँचे (Inverted Duty) को ठीक किया गया है।
3. जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) को विवादों के शीघ्र निपटान हेतु क्रियान्वित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Ans : d)

UPSC Mains Practice Question

Ques: जीएसटी 2.0 सुधारों को केवल कर सुधार नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक सुधार माना जा रहा है। इनका परिवारों, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (MSME) तथा भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर संभावित प्रभावों की विवेचना कीजिए। (150 words)

अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क लगाने से भारत के निर्यात-निर्भर क्षेत्रों की कमजोरी उजागर हुई है। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि निर्यात को घरेलू बाजार में मोड़ा जाए, लेकिन व्यापार विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि चेतावनी देते हैं कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच संरचनात्मक अंतर, कम अवशोषण क्षमता और उत्पाद-विशेष बाधाओं के कारण यह संक्रमण चुनौतीपूर्ण है। इसके बजाय, वैश्विक बाजारों में विविधीकरण और सरकार की नीति समर्थन लंबी अवधि की अधिक व्यवहार्य रणनीति है।

मुख्य बिंदु

1. घरेलू बाजार में स्थानांतरण की चुनौतियाँ

- **अधिक आपूर्ति और मूल्य-संवेदनशीलता:** हीरे, आभूषण और कालीन जैसी उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार की क्षमता सीमित है। मौजूदा खिलाड़ी पहले ही भारी छूट के कारण दबाव में हैं।
- **बाजार विनिर्देश और मांग पैटर्न:** निर्यात बाजार मानकीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन की मांग करते हैं, जबकि घरेलू मांग क्षेत्रीय रूप से भिन्न होती है और अलग पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण या वितरण चैनल की आवश्यकता होती है।
- **संचालनात्मक व्यय:** निर्यात-उन्मुख कंपनियाँ विदेशी मांग के लिए अनुकूलित बिजनेस मॉडल पर काम करती हैं। घरेलू बाजार में प्रवेश के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता हो सकती है।

कुछ क्षेत्रों में सीमित अवसर

- हस्तशिल्प और फुटवियर जैसी कम मूल्य वाली वस्तुएँ घरेलू बाजार में कुछ संभावनाएँ पा सकती हैं।
- जीएसटी दरों का सुधार कुछ क्षेत्रों में घरेलू मांग को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन समग्र प्रभाव सीमित है।

Not easy to switch to domestic from global, say exporters

Trade experts/exporters say global market diversification is a more feasible option but can't happen overnight and will need govt. support

Amiti Sen
NEW DELHI

Multiple factors, such as low surplus absorption capacity and different specifications, severely inhibit a shift to the domestic market for exporters struggling to sell in the U.S. because of the 50% tariffs.

Trade experts and exporters believe international market diversification is a more feasible option, but even that cannot happen overnight and would need active support from the government.

Market stress

"Diverting export products to the domestic market is not a big possibility as there is oversupply. Already, all domestic players are under stress, as you can see from their heavy discounts. International market diversification is definitely a solution, but it is not an immediate option," pointed out Sanjay Jain, chairman, ICC National Textiles Committee.

Rationalisation of GST rates could expand the domestic market for some sectors such as footwear, but not for others like diamonds and jewellery, because for every product, the domestic market's capacity to absorb will be different, explained Ajay Sa-



Tough times: The domestic market cannot substitute the export market for India, says Mr. Dhar. REUTERS

hai of FIEO. "For low-value items like some handcrafts, there might be demand in the domestic market, but for high-value items like carpets, the capacity to absorb may be limited due to high price and because it is not a fast-moving item," he said.

Long-term solution

Thirukkumaran Natarajan, chairman of Tiruppur-based Esstee Exports India Pvt. Ltd., said diversifying to domestic markets can only be a long-term solution. "The set-up is different for exports and domestic (demand) as markets are different and overheads are also different," said Mr. Natarajan, who is also the Secretary of Tiruppur Exporters Association.

Exporters need to keep supplying to their foreign markets to retain the major

brands that source supplies from them, said Mithileshwar Thakur of AEPC.

"If exporters stop supplying to major foreign brands, they may just leave. So, exporters will try their best to retain them," Mr. Thakur said.

The domestic market cannot substitute the export market for India, pointed out Biswajit Dhar from the Council for Social Development.

"India is a hugely import-dependent country. We need the foreign exchange," he said. Mr. Dhar added that the best way to deal with the loss of U.S. market would be to diversify to newer markets in Africa, Latin America and Central Asia and the Centre should provide all support.

(The writer is with The Hindu Businessline. Inputs from T.E. Raja Simhan.)

दीर्घकालिक रणनीति: बाजार विविधीकरण

- निर्यात को वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों—अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया—में विस्तारित करना दीर्घकालिक समाधान माना जाता है।
- स्थापित विदेशी ब्रांडों को निरंतर आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है; इन अनुबंधों का नुकसान स्थायी नुकसान का कारण बन सकता है।
- सरकार का समर्थन—व्यापार सुविधा, प्रोत्साहन और निर्यात संवर्धन—नई बाजारों में तेजी से प्रवेश के लिए आवश्यक है।

आर्थिक निहितार्थ

- भारत अभी भी आयात पर निर्भर है; निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है।
- घरेलू बाजार में तत्काल रीडायरेक्शन खोई हुई निर्यात आय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, जिससे रणनीतिक बाजार विविधीकरण और नीति समर्थन की आवश्यकता बढ़ जाती है।

निष्कर्ष

वर्तमान अमेरिकी शुल्क भारत के निर्यात क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियों और घरेलू विकल्पों की सीमाओं को उजागर करते हैं। जबकि घरेलू बाजार में सीमित राहत संभव है, वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विविधीकरण और सरकारी प्रोत्साहन दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान प्रदान करता है। नीति हस्तक्षेप को क्षेत्र-विशेष विशेषताओं, घरेलू अवशोषण क्षमता और विदेशी ग्राहक संबंधों की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और विदेशी मुद्रा स्थिरता सुरक्षित रहे।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: निम्नलिखित में से कौन सा GST 2.0 सुधार का हिस्सा नहीं है?

- दरों का सरलरण और संशोधन
- छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए स्वचालित पंजीकरण
- निर्यात पर 50% कर लगाया जाना
- GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का संचालन

Ans : c)

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारतीय निर्यातकों को घरेलू बाजार की ओर रुख करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और दीर्घकालिक समाधान क्या सुझाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। (150 Words)

Page : 08 Editorial Analysis

India's strategic autonomy in a multipolar world

In the lexicon of international relations, few concepts have evolved as dynamically as "strategic autonomy". Once a term confined to academic debate, it now sits at the heart of India's foreign policy discourse, shaping decisions in an increasingly multipolar and volatile world. As global power shifts accelerate and traditional alliances fray, India finds itself navigating a delicate path between competing giants: the United States, China and Russia. The pursuit of strategic autonomy is no longer a theoretical aspiration. It is a daily diplomatic practice, fraught with complexity and consequence.

Strategic autonomy refers to a nation's ability to make sovereign decisions in foreign policy and defence without being constrained by external pressures or alliance obligations. It is not synonymous with isolationism or neutrality. Rather, it implies flexibility, independence and the capacity to engage with multiple powers on one's own terms. For India, the concept has deep historical roots, going back to colonial subjugation and free India's determination never to let anybody else decide our place in the world for us. From Nehru's non-alignment during the Cold War to the Modi government's "multi-alignment" in the current era, successive governments have sought to preserve India's freedom of action while adapting to changing geopolitical realities. In theory, strategic autonomy offers a middle path between rigid bloc politics and passive disengagement. In practice, it demands deft diplomacy, institutional resilience, and a clear-eyed understanding of national interest. It is a balancing act – sometimes precarious, often imperfect, but essential for a country such as India that aspires to global leadership without becoming a client state.

The current global landscape presents both opportunities and challenges for India's strategic autonomy. The unipolar moment of American dominance has given way to a fragmented world order, where China's assertiveness, Russia's revisionism and the West's internal divisions, accentuated by Washington's unpredictability, create a fluid and unpredictable environment. For India, this means recalibrating its relationships with major powers while safeguarding its core interests – territorial integrity, economic growth, technological advancement, and regional stability.

India's relationship with the United States has deepened dramatically over the past two decades. From defence cooperation and intelligence sharing to joint military exercises and technology transfers, the strategic partnership has matured. The Quad grouping (Australia, Japan, India, the U.S.), Indo-Pacific dialogues, the Incipient I2U2 (India, Israel, the United Arab Emirates and the U.S.) and India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), and shared concerns over China's rise have further



Shashi Tharoor

is a fourth-term Member of Parliament, Congress (Lok Sabha) from Thiruvananthapuram, is chairman of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs, and the author of 'Pax Indica: India and the world of the 21st century'

As the global order shifts, India must continue to walk the tightrope, treading a delicate path between the United States, China, and Russia

cemented ties. Yet, the relationship is not without friction. The Trump administration's erratic trade policies, followed by stinging tariffs and sanctions in his second term, have strained economic ties. Washington's pressure on India to reduce its energy and defence dealings with Russia, and to align more closely with western positions, has tested New Delhi's resolve.

India's response has been measured. It continues to engage with the U.S., maintains independent positions on global conflicts, and insists on the primacy of national interest over ideological alignment. This is strategic autonomy in action, not anti-Americanism, but a refusal to be subsumed by American priorities.

Ties with Beijing and Moscow

China presents a more complex challenge. The border clashes with India of 2020 shattered illusions of benign coexistence, and tensions remain high despite diplomatic overtures. Yet, China is also one of India's largest trading partners, a key player in regional institutions, and a competitor whose actions shape the strategic environment. India's approach is one of cautious engagement and firm deterrence. It strengthens border infrastructure, deepens ties with Indo-Pacific partners, and invests in indigenous defence capabilities. At the same time, it participates in multilateral forums such as BRICS and the Shanghai Cooperation Organisation, where China plays a leading role – a difficult but necessary balancing act.

Strategic autonomy here means resisting both confrontation and capitulation. It means asserting sovereignty and refusing to be another country's counterweight to a rising China, while controlling Chinese access to the Indian economy, and simultaneously keeping channels of communication open. It means recognising that rivalry does not preclude diplomacy, and that decoupling is not always desirable or feasible.

India's relationship with Russia is rooted in Cold War solidarity, defence cooperation and shared strategic interests. Despite Moscow's growing closeness to Beijing and Russia's global isolation following the Ukraine conflict, India has maintained its ties – buying oil, importing weapons, and engaging diplomatically. This has drawn criticism from western capitals, but India has stood firm. Its relationship with Russia is historical, multidimensional and not subject to external veto. It continues to diversify its military imports, invest in indigenous production and explore new partnerships, but without abandoning old ones. Strategic autonomy here is about refusing to choose sides in a binary contest, and, instead, crafting a foreign policy that reflects India's unique geography, history and aspirations.

During India's G-20 presidency in 2023, Prime Minister Narendra Modi declared that India was now the voice of the Global South – unbowed,

plural and potent. Its democracy, he said, was not just a system but a "bouquet of hope", nourished by the strength of its multilingual, multicultural fabric. External Affairs Minister S. Jaishankar argues that partnerships must be shaped by interest, not sentiment or inherited bias. This is diplomacy with a spine – assertive, pragmatic, and unapologetically Indian, seeking to be "non-West" without being "anti-West". This stance resonates across the Global South, where many rising and middle powers concerned with peace and stability in their own regions, are choosing to safeguard their geopolitical and economic interests rather than be swept into the vortex of great-power rivalries. They seek agency, not alignment; voice, not vassalage.

What emerges is a vision of India as a sovereign pole in a rebalancing world – a nation that neither aligns blindly nor isolates itself. India's rise, then, is civilisational, plural and deeply political. While India's pursuit of strategic autonomy is principled, it faces headwinds as it walks the tightrope among the major powers. The global economy is increasingly interdependent, and technological ecosystems are dominated by a few players. Defence modernisation requires partnerships and climate diplomacy demands coordination. In such a world, autonomy must be redefined – not as isolation, but as resilience and adaptability.

Domestic factors also play a role. Political polarisation, economic vulnerabilities and institutional constraints can limit the effectiveness of autonomous decision-making. Strategic autonomy requires not just diplomatic skill, but economic strength, technological capability and political coherence. We cannot be truly autonomous from a position of weakness.

Moreover, in a world of cyber threats, Artificial Intelligence warfare and space competition, autonomy must extend beyond traditional domains. It must encompass data sovereignty, digital infrastructure and supply chain security. India's recent efforts to build indigenous platforms, secure critical minerals and assert its voice in global tech governance are steps in this direction.

More than a slogan

Strategic autonomy is not just a slogan. It is a strategy. It is the art of navigating a turbulent world without losing one's bearings. As the global order shifts, India must continue steadily to walk the tightrope – engaging with the U.S. without becoming a vassal, deterring China without provoking war, and partnering with Russia without inheriting its isolation. It must invest in capabilities, cultivate partnerships, and assert its interests with clarity and confidence.

In doing so, India does not reject the world – it reclaims its agency within it. Strategic autonomy is not about standing alone; it is about standing straight, and standing tall.

GS. Paper 02 - International Relations

UPSC Mains Practice Question: भारत की बहुध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसे हालिया अमेरिकी, चीन और रूस संबंधों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। (150 Words)

Context :

रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) आज भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु बन गई है। इसका अर्थ है कि कोई देश बिना बाहरी दबाव या गठबंधन के बंधनों के, अपने कूटनीतिक और रक्षा संबंधी निर्णय स्वयं ले सके। भारत के लिए यह अवधारणा ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान महत्वाकांक्षा और बड़ी शक्तियों—यू.एस., चीन और रूस—के साथ जटिल संबंधों को संतुलित करने की व्यावहारिक आवश्यकता पर आधारित है।

मुख्य बिंदु**1. रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ**

- यह तटस्थता या अलगाववाद नहीं है, बल्कि लचीलापन, स्वतंत्रता और बहुपक्षीय संबंधों में अपनी शर्तों पर भागीदारी का संकेत है।
- ऐतिहासिक रूप से, भारत की शीत युद्ध काल की गैर-संरेखण नीति (Non-alignment) से यह वर्तमान “मल्टी-अलाइनमेंट” (Multi-alignment) नीति में विकसित हुई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध

- गहरी रणनीतिक साझेदारी: रक्षा सहयोग, खुफिया साझा करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्वाड, I2U2 और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा।
- चुनौतियाँ: अमेरिकी टैरिफ, व्यापार दबाव, रूस के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण।
- भारत की प्रतिक्रिया: राष्ट्रीय हित प्राथमिकता, अमेरिकी दबावों के अधीन न होना, जिससे स्वायत्तता का उदाहरण सामने आता है।

चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन

- जटिल स्थिति: 2020 की सीमा संघर्षों के बावजूद व्यापार और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग (BRICS, SCO) जारी है।
- रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है संप्रभुता बनाए रखना, हतोत्साहित किए बिना कूटनीतिक संवाद और मजबूत प्रत्याशा।
- विरोध या अधीनता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक।

रूस के साथ संबंध

- ऐतिहासिक साझेदारी: रक्षा उपकरण, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक हित।
- पश्चिमी दबाव और रूस के वैश्विक अलगाव के बावजूद, भारत ने रिश्ते बनाए रखे।
- स्वायत्तता का अर्थ है बाहरी दबाव को स्वीकार किए बिना दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित सुनिश्चित करना।

व्यावहारिक पहलू

- वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व के रूप में भारत की भूमिका: बहुपक्षीयता और संप्रभु एजेंसी का प्रतिनिधित्व।
- आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता: डेटा संप्रभुता, साइबर सुरक्षा, AI और अंतरिक्ष सुरक्षा।
- घरेलू कारक: राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक शक्ति और संस्थागत मजबूती।

अवसर और चुनौतियाँ

- बहुध्रुवीयता भारत को कठोर गठबंधनों में न बँधते हुए कई शक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध बनाने का अवसर देती है।
- चुनौतियाँ: वैश्विक आर्थिक अंतरनिर्भरता, तकनीकी असमानताएँ और घरेलू कमजोरियाँ।
- प्रभावी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए कूटनीति, क्षमता निर्माण और सिद्धांत आधारित निर्णय आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि दुनिया की जटिल परिस्थितियों में चलने की रणनीति है। इसका अर्थ है:

- अमेरिका के साथ सहयोग करना, लेकिन अधीन नहीं होना।
- चीन को मुकाबला देना, लेकिन युद्ध के जोखिम के बिना।
- रूस के साथ साझेदारी बनाए रखना, लेकिन इसके वैश्विक अलगाव को अपनाए बिना।

यह स्वायत्तता केवल अलग खड़े होने का नहीं, बल्कि अपने निर्णयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीय हित में दृढ़ता और वैश्विक मंच पर सम्मानपूर्ण उपस्थिति बनाए रखने का नाम है।